न्यूज डायरी

काबुल पर तालिबान का कब्जा अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बिना किसी विरोध के तालिबान का काबुल पर कब्जा अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ बाइडन ने जो किया, वह ऐतिहासिक है। तालिबान का काबुल में राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा होने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संक्षिप्त बयान यह बात कही है। काबुल में तेजी से बदले घटनाक्रम पर व्हाइट हाउस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राष्ट्रपति जो बाइडन इस दौरान कैंप डेविड में सप्ताहांत की छुट्टी मना रहे थे। उन्होंने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बैठक की है। अमेरिका की पूर्व में संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रहीं निक्की हेली ने काबुल पर तालिबान के कब्जे को बाइडन प्रशासन की असफलता बताया है। उन्होंने कहा कि वहां से सुरक्षित निकलने की तालिबान से भीख मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है।

इमरान खान सरकार के पाकिस्तान में तीन वर्ष हुए पूरे

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर उसने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस रिपोर्ट कोर्ड के जरिए देश में नया पाकिस्थान का नारा देने वाले इमरान खान की काबलियत को भी आसानी से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इमरान खान की सरकार के दौरान देश में न सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ी है बल्कि देश में खाने–पीने की जरूरी चीजों के दामों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसी माह इमरान खान ने गैस, तेल और डीजल के दामों में तेजी कर आम आदमी की जेब पर और अधिक बोझ डालने का एलान किया था। इसके बाद भी जरूरी चीजों के दामों में तेजी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि वर्तमान में पाकिस्तान न सिर्फ कोरोना महामारी से जूझ रहा है, बल्कि देश में पानी और बिजली की भी जबरदस्त किल्लत हो रही है।

मलेशिया में राजनीतिक बवाल, प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन की सरकार गिरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने सत्ता संभालने के 18 महीने से भी कम समय पहले, सोमवार को मलेशिया के नरेश को इस्तीफा सौंप दिया। वह देश की सत्ता में सबसे कम समय तक आसीन रहे नेता बन गए हैं। वह मार्च 2020 में प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले उन्होंने यह स्वीकार किया था कि शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। विज्ञान मंत्री खैरी जमालुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मंत्रिमंडल ने नरेश को इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले यासीन सोमवार को मलेशिया नरेश से मिलने राजमहल पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उप खेल मंत्री वान अहमद फयहसल वान अहमद कमाल ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी जिसमें मुहिउद्दीन के नेतृत्व और सेवा के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, भारत से समर्थन की उम्मीद करता है संगठन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। तालिबान के प्रवक्ता शाहीन सुहैल का कहना है कि संगठन उम्मीद करता है कि भारत अपना रुख बदलेगा और तालिबान का समर्थन करेगा। प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में श्पुनर्निर्माणश के लिए तालिबान के रोडमैप सहित कई अन्य मुद्दों पर यह बात कही। सुहैल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत भी अपनी नीतियों में बदलाव करेगा क्योंकि पहले वे एक थोपी गई सरकार का पक्ष ले रहे थे। यह दोनों पक्षों, भारत और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। राजधानी में समूह के दाखिल होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था, जिसके बाद लड़ाकों ने राष्ट्रपति महल को अपने कब्जे में ले लिया। काबुल की स्थिति पर सुहैल ने कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए काबुल शहर में प्रवेश किया है।

मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना चाहता हैं, क्या खुद को बचा रहा है ड्रैगन?

तालिबान को लेकर चीन का बड़ा बयान

बयान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

बीजिंग। दुनिया भर के लोग अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा किए जा रहे कृत्य को देखकर आहत हैं। तालिबान द्वारा रविवार को काबुल पर कब्जा कर लिया गया और फिर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर तजाखिस्तान चले गए हैं। इसके बाद वहां खौफ का माहौल है और अफगान में रह रहे लोग काबुल छोड़ने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। तालिबान के डर से लोग काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गए हैं। देश में तालिबान द्वारा किए जा रहे अत्याचार के बीच चीन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन का कहना है कि वह तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है।

चीन ने सोमवार को कहा कि वह तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध विकसित करने के लिए तैयार है। बता दें कि इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद चीन के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है, ऐसे में इस दोस्ती के पीछे भी चीन की कोई चाल ना हो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने संवाददाताओं से कहा, चीन स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने में समर्थ होने के अफगान लोगों के अधिकार का सम्मान करता है और अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध विकसित करना जारी रखना चाहता है। बता दें कि चीन अफगानिस्तान के साथ 76 किलोमीटर (47 मील) की एक ऊबड़–खाबड़ सीमा साझा करता है।. ..और बीजिंग को लंबे समय से डर है कि शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यक उइगर अलगाववादियों के लिए अफगानिस्तान एक मंच बन सकता है।

हालांकि, तालिबान के एक शीर्ष स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने तियानजिन में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जिसमें वादा किया गया कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों के बेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बदले में, चीन ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता और निवेश की पेशकश की थी।

बता दें कि शिनजियांग अफगानिस्तान के साथ एक संकरी सीमा साझा करता है और बीजिंग अपनी सीमा पर हिंसा फैलाने के डर से चिंतित है। चीन को लगता है कि तालिबान अफगानिस्तान पर नियंत्रण ले लेता है तो चीन में क्षेत्रों में हलचल तेज हो जाएगी। शिनजियांग में चीन ने 10 लाख से अधिक उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सदस्यों को आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया है।

काबुल के स्थानीय निवासियों से हथियार ले रहा तालिबान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थानीय लोगों से हथियारों को एकत्रित करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को अब अपनी सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत नहीं है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, श्हम इस बात को समझते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखते हैं। अब वे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हम निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

शहर के निवास सलाद मोलेस्किन ने ट्विटर पर बताया कि तालिबान के लोग उनकी कंपनी के कंपाउंड में आए और सिक्योरिटी टीम के पास हथियारों की जानकारी ली। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पल–पल हालात बदल रहे हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य नेता एवं राजनयिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन एआरजी को अपने कब्जे में ले लिया है। पहले आंतरिक सरकार के गठन की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तालिबान ने अंतरिम सरकार की संभावनाओं को खारिज कर दिया। तालिबान के एक अधिकारी ने जल्द ही अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात आफ अफगानिस्तान घोषित किए जाने की बात कही है।

अफगान मूल के लोगों का व्हाइट हाउस पर प्रदर्शन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन पर अफगानिस्तान की जनता के साथ धोखा करने और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर व्हाइट हाउस पर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों अफगान मूल के लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों में सबसे ज्यादा नाराजगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों को लेकर थी। यह प्रदर्शन अफगानिस्तान से राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाग जाने और सरकारी अधिकारियों के द्वारा तालिबान को राष्ट्रपति पैलेस सौंपे जाने के बाद किया गया। यहां प्रदर्शन करने वाले फरजाना हाफिज ने बताया कि अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर फिर ताले लगा दिए गए।

तालिबान के कब्जे के बाद यूएन को भी सता रही महिलाओं की चिंता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

न्यूयार्क। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। संगठन के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में जो प्रगति देखने को मिली थी वो खत्म हो सकती है। उन्होंने भविष्य में वहां पर महिलाओं के हकों को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में बीते दो दशकों के दौरान जो तरक्की हासिल हुई थी उसकी रक्षा की जानी चाहिए और उनके अधिकारों का हर हाल में बचाव किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि

महिलाओं के हकों को लेकर भी चिंता जताई

अफगानिस्तान वर्ष 2001 से पहले और बाद में भी काफी समय तक तालिबान की क्रूरता को झेल चुका है। तालिबान शासन की सबसे अधिक मार अफगान महिलाओं पर ही पड़ी थी।

तालिबान के दौर में महिलाओं का अकेले घर से बाहर निकलना, उच्च शिक्षा हासिल करना, बाहर काम करना, संगीत सुनना, मैच देखना, अकेले विदेश यात्रा पर जाना प्रतिबंधित था। तालिबान के नियमों का पालन न करने वालों को सरे आम सजा दी जाती थी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले ही यहां की चुनी गईं महिला सांसदों ने भी इस तरह की ही आशंका जताई थी तालिबान का शासन स्थापित होने से एक बार फिर से देश के पुराने बुरे दिन वापस आ सकते हैं।

अब यही बात गुतारेस ने भी कही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को हर हाल में रोकना होगा। तालिबान की हुकूमत में अफगान महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कई सारी घटनाएं सामने आई थीं। गुतारेस ने इन सभी का जिक्र करते हुए कहा है कि तालिबान समेत दूसरे सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करना चाहिए। देशवासियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।

तालिबान के लिए अफगानिस्तान की सत्ता होगी कांटों का ताज

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। करीब 30 साल पहले तालिबान एक आंदोलन की शक्ल में पैदा हुआ था और तब उसका अफगानिस्तान की जनता से वादा था कि भ्रष्ट और अस्थिर सरकार से छुटकारा दिलाएगा। आखिरकार 15 अगस्त, 2021 को इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने अशरफ गनी सरकार को हटा दिया और सत्ता हासिल कर ली। हालांकि, तालिबानी आंदोलन यहां खत्म नहीं हुआ है बल्कि जो वादा इतने साल से यह संगठन करता रहा, उसका इम्तिहान होना बाकी है। नवभारत टाइम्स ऑनलनाइन से बातचीत में डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा ने कहा है कि तालिबान देश की कमान संभाल नहीं पाएगा और यहां अराजकता फैलते देर नहीं लगेगी। कमर आगा का कहना है कि तालिबान ने पूरा मुल्क कब्जा कर लिया है लेकिन उसके पास पब्लिक सपॉर्ट नहीं है। इसके उलट आम जनता तालिबान के साथ नहीं बल्कि डरी हुई है कि उनका क्या होगा। देश से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं और मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं।